



एग्री मैगज़ीन

(कृषि लेखों के लिए अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिका)

वर्ष: 03, अंक: 04 (अप्रैल, 2026)

www.agrimagazine.in पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री मैगज़ीन, आई. एस. एन.: 3048-8656

ई-नाम (e-NAM) का आर्थिक विश्लेषण: कृषि विपणन में मध्यस्थता उन्मूलन और कृषक आय संवर्धन

*नितिन मौर्य, अनामिका यादव, यशोधन गुप्ता एवं अभिषेक मिश्रा

स्नातकोत्तर छात्र, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश-224229, भारत

*संवादी लेखक का ईमेल पता: economistniti@gmail.com

भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला होने के बावजूद, कृषि क्षेत्र लंबे समय से विपणन की विसंगतियों से जूझ रहा है। पारंपरिक APMC (कृषि उपज मंडी समिति) मंडियों में सूचना की विषमता (Information Asymmetry), बिचौलियों का एकाधिकार और पारदर्शी मूल्य खोज तंत्र का अभाव किसानों के आर्थिक शोषण का मुख्य कारण रहा है। इस परिदृश्य को बदलने हेतु 14 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) का शुभारंभ किया गया। यह केवल एक डिजिटल पोर्टल नहीं, बल्कि कृषि विपणन व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने वाला एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन है।

विस्तार और वर्तमान सांख्यिकीय स्थिति (मार्च 2026 तक): नवीनतम सरकारी आंकड़ों (PIB, मार्च 2026) के अनुसार, e-NAM ने अपनी पहुँच और व्यापार मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है:

- मंडियों का एकीकरण: वर्तमान में 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,656 मंडियां इस पोर्टल से जुड़ चुकी हैं।
- पंजीकरण: लगभग 1.80 करोड़ किसान, 2.73 लाख व्यापारी और 4,724 किसान उत्पादक संगठन (FPOs) इस प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं।
- व्यापार मूल्य: वर्ष 2016 से मार्च 2026 तक संचयी व्यापार मूल्य ₹4.84 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, जो 2024 (₹3.19 लाख करोड़) की तुलना में भारी वृद्धि दर्शाता है।

e-NAM की प्रगति और विकास का तुलनात्मक विवरण (मार्च 2026 तक)

विवरण (Description)	सांख्यिकीय आंकड़े (Current Stats)	तुलनात्मक वृद्धि / टिप्पणी
एकीकृत मंडियों की संख्या	1,656	23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत नेटवर्क
पंजीकृत किसान	~1.80 करोड़	भारतीय कृषि का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क
पंजीकृत व्यापारी	2.73 लाख	स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए
किसान उत्पादक संगठन (FPOs)	4,724	सामूहिक सौदेबाजी की बढ़ती शक्ति
संचयी व्यापार मूल्य (2024)	₹3.19 लाख करोड़	आधारभूत तुलनात्मक डेटा
संचयी व्यापार मूल्य (2026)	₹4.84 लाख करोड़	₹1.65 लाख करोड़ की शुद्ध वृद्धि (2024 से)
प्रतिशत वृद्धि (2024-2026)	~51.72%	डिजिटल विपणन में अभूतपूर्व उछाल

1. मध्यस्थता उन्मूलन: बिचौलियों के वर्चस्व का अवसान

पारंपरिक विपणन प्रणाली में 'आढ़तियों' और बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला होती है, जो किसान के शुद्ध लाभ का एक बड़ा हिस्सा 'कमीशन' के रूप में ले लेते हैं। e-NAM का आर्थिक तंत्र निम्नलिखित तरीकों से इसे समाप्त करता है:

- प्रत्यक्ष व्यापार: e-NAM किसानों को सीधे व्यापारियों और निर्यातकों से जोड़ता है, जिससे मध्यस्थों की भौतिक आवश्यकता कम हो जाती है।
- पारदर्शी ई-नीलामी: इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि मूल्य का निर्धारण आपसी मिलीभगत के बजाय बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर हो।

- लागत में कमी: e-NAM मंडियों में लेनदेन की लागत (Transaction Costs) में उल्लेखनीय गिरावट आई है, क्योंकि डिजिटल लेनदेन ने छिपे हुए शुल्कों (Hidden Charges) को समाप्त कर दिया है।

2. पारदर्शी मूल्य खोज और गुणवत्ता मूल्यांकन

e-NAM की सबसे बड़ी आर्थिक विशेषता इसकी गुणवत्ता-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली है।

- गुणवत्ता जांच: पोर्टल पर उपज की लैब-परीक्षण रिपोर्ट अपलोड की जाती है। जब खरीदार को उपज की गुणवत्ता का सटीक पता होता है, तो वह उच्च गुणवत्ता वाली फसल के लिए बेहतर प्रीमियम देने को तैयार होता है।
- अखिल भारतीय बाजार तक पहुँच: पहले किसान केवल स्थानीय मंडी के भावों पर निर्भर था। अब e-NAM के माध्यम से, उत्तर प्रदेश का एक किसान (जैसे प्रतापगढ़ का आँवला उत्पादक) तमिलनाडु के खरीदार से बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकता है।

3. कृषक आय संवर्धन: सांख्यिकीय साक्ष्य और प्रभाव

मार्च 2026 तक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, e-NAM का प्रभाव भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है:

- आय में वृद्धि: विभिन्न केस स्टडीज (जैसे तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले) में पाया गया है कि e-NAM के माध्यम से बेचने वाले किसानों की आय में पारंपरिक पद्धति की तुलना में 15% से 20% तक की वृद्धि हुई है।
- शीघ्र भुगतान : प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में 24 से 48 घंटों के भीतर पहुँच जाता है, जिससे उनकी तरलता (Liquidity) बढ़ती है और महाजनों पर उनकी निर्भरता घटती है।
- व्यापार का पैमाना: मार्च 2026 तक लगभग 1,656 मंडियाँ एकीकृत हो चुकी हैं और ₹4.84 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार इस प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया गया है, जो इसकी बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण है।

4. वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँ और सीमाएँ

भले ही e-NAM ने संरचनात्मक सुधार किए हैं, लेकिन पूर्ण दक्षता प्राप्त करने में कुछ बाधाएँ अभी भी शेष हैं:

- डिजिटल विभाजन: छोटे और सीमांत किसानों में तकनीकी साक्षरता की कमी।
- बुनियादी ढांचा: कई मंडियों में अभी भी अत्याधुनिक ग्रेडिंग और सॉर्टिंग मशीनों का अभाव है।
- परिवहन लागत: अंतर-राज्यीय व्यापार में लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत छोटे किसानों के लिए अभी भी एक चुनौती है।

निष्कर्ष

e-NAM भारतीय कृषि विपणन के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह बिचौलियों द्वारा होने वाले आर्थिक रिसाव को रोकते हुए मूल्य को सीधे किसान तक पहुँचाने का माध्यम बन गया है। यदि भविष्य में इसे किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और सुदृढ़ कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स प्रणाली के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत कर दिया जाए, तो यह कृषक आय वृद्धि के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने वाला सबसे सशक्त स्तंभ सिद्ध होगा।

संदर्भ

1. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), भारत सरकार (मार्च 2026): राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) की प्रगति रिपोर्ट: एक दशक का आर्थिक विश्लेषण और उपलब्धियाँ। <https://enam.gov.in>
2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (2025-26): e-NAM पोर्टल सांख्यिकी: किसान पंजीकरण, मंडी एकीकरण और व्यापार मूल्य का वार्षिक विवरण। <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx>
3. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) 2025-26: कृषि विपणन में डिजिटल सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन - अध्याय: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey>
4. लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC): e-NAM के कार्यान्वयन की मार्गदर्शिका और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की भूमिका। <https://sfacindia.com/Nam.aspx>
5. राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान (NIAP): विभिन्न राज्यों (तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) में e-NAM के प्रभाव का केस स्टडी विश्लेषण, 2025 <https://www.google.com/search?q=https://krishikosh.egranth.ac.in/handle/1/NIAP>